माननीय न्यायमूर्ति बलराज तुली के समक्ष

पंजाब राज्य और अन्य *(प्रतिवादी) - अपीलकर्ता*

बनाम

लाल चंद *(वादी) - प्रतिवादी।*

1962 की नियमित प्रथम अपील संख्या 17

10 फरवरी, 1975।

*भारतीय परिसीमा अधिनियम (*1908 का IV) - *अनुच्छेद 2 और 22 - दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का V) - धारा 149 - पुलिस अधिनियम (*1861 का V) - धारा 23 - कानून *का कानून - हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को किसी स्थान पर तितर-बितर करने के लिए ले जाने वाले पुलिस अधिकारी - ऐसे अधिकारी - चाहे धारा 149 या धारा 23 द्वारा लगाए गए कर्तव्यों के पालन में कार्य कर रहे हों - पुलिस वैन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को घायल कर देती है - मुआवजे के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मुकदमा - चाहे वह अनुच्छेद 22 द्वारा शासित हो - राज्य - क्या उत्तरदायी - पुलिस वैन का चालक - क्या राज्य की प्रत्यायोजित संप्रभु शक्ति का उपयोग करता है।*

यह माना गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 149 के तहत एक पुलिस अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के प्रयोजनों के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन जहां किसी व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और हिरासत में लिया गया है और उसे किसी स्थान पर तितर-बितर करने

के लिए पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, न कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के लिए, तो पुलिस अधिकारी को प्रदर्शन में कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता है। संहिता द्वारा राज्य और पुलिस पर लगाए गए कर्तव्यों की संख्या। संहिता की धारा 127 और 128 भी उस समय लागू नहीं होती हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ले जाने में पुलिस की कार्रवाई भारत में फिलहाल लागू किसी भी अधिनियमन के अनुसरण में नहीं है। इसी तरह पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 23 भी ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं है।. यदि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को ले जाते समय पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से कोई भी घायल हो जाता है, तो ऐसे घायल व्यक्ति द्वारा मुआवजे के लिए दायर मुकदमा व्यक्ति को चोट के मुआवजे के लिए होगा और यह परिसीमा अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 22 द्वारा शासित होगा। यदि दुर्घटना की तारीख के एक वर्ष के भीतर ऐसा मुकदमा दायर किया जाता है, तो यह समय के भीतर होगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह सत्य है कि राज्य में कानून और व्यवस्था का संरक्षण राज्य का संप्रभु कार्य है, लेकिन किसी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके तितर-बितर करने की दृष्टि से राज्य की पसंद के स्थान पर पहुँचाना एक संप्रभु कार्य नहीं कहा जा सकता है।

जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, उसके साथ देश के कानून के तहत व्यवहार किया जाना है, न कि राज्य के अधिकारियों की सनक के अनुसार। किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तितर-बितर करने के लिए कहीं और ले जाने के लिए अधिकृत करता है। इस प्रकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस वैन में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने को राज्य के संप्रभु कार्यों के

निष्पादन में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, पुलिस वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हुई चोट के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी।

श्री एच. एस. अहलूवालिया, अतिरिक्त उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अंबाला सिटी, दिनांक 3 अक्टूबर, 1961 के न्यायालय के डिक्री से नियमित प्रथम अपील, जिसमें वादी को प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के विरुद्ध 40,000 रुपये के भुगतान के लिए डिक्री प्रदान की गई है और दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी के संबंध में 10,000 रुपये के वाद को खारिज किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद में निर्धारित राशि के आनुपातिक व्यय का भुगतान करेगा और उस राशि के संबंध में व्यय की वसूली करेगा जिसके लिए इसे खारिज कर दिया गया था और श्री कौल के विरुद्ध वादी के वाद को आगे खारिज कर दिया गया और व्यय के रूप में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता एस. के. सयाल के साथ महाधिवक्ता (पंजाब) जे. एस. वासु।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता डी. सी. अहलूवालिया।

अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट-जनरल (पंजाब) जे. एस. वासु और एडवोकेट एस. के. सयाल *मौजूद थे।*

प्रतिवादी की ओर *से अधिवक्ता डीसी अहलूवालिया .*

निर्णय

तुली, न्यायाधीश-लाल चंद सभरवाल (वादी-प्रतिवादी) ने निम्नलिखित मामलों में

हर्जाने के कारण 50,000 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया:-

(1) पेशेवर प्रैक्टिस के नुकसान और वास्तविक चिकित्सा खर्च के लिए 10,000 रुपये,

(2) बाएं कंधे, कोहनी, हाथ, आंख में कमजोरी और उससे होने वाली सभी मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं सहित बाएं हाथ की स्थायी विकलांगता के कारण 30,000 रुपये, और

(3) अवैध गिरफ्तारी, गलत तरीके से कारावास, अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न के कारण 10,000 रुपये।

तथ्यों में कहा गया था कि वादी भारतीय जनसंघ, पंजाब राज्य का उपाध्यक्ष था, जिसने कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से मई, 1957 में पंजाब राज्य में 'हिंदी बचाओ' आंदोलन शुरू किया था। वादी ने इस शांतिपूर्ण मिशन के लिए खुद को प्रस्तुत किया और 15 जुलाई, 1957 को लगभग 4 A.M. पर 250 स्वयंसेवकों के एक बैच के साथ ट्रेन से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। पहुंचने पर, उन्हें और उनकी पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रतिवादी नंबर 2, सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री ए. के. कौल के आदेश पर पुलिस बल के अनुरक्षण में विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया।

वादी और उसके छह साथियों को बिना किसी पानी और भोजन के सांपों से प्रभावित क्षेत्र के चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था और उनके साथ सबसे अमानवीय व्यवहार किया गया था।लगभग आधी रात को वादी और उसके साथियों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्री ए. सी. तुली के आदेश पर पुलिस अनुरक्षण में एक बस में चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन से अंबाला शहर की ओर एक अज्ञात गंतव्य पर ले जाया गया। रास्ते में उन्हें पुलिस वैन नं. पी. एन. ई. 4615 और

वादी को सामने की सीट पर बैठा दिया गया और ड्राइवर को श्री ए. सी. तुली, मजिस्ट्रेट ने उसकी जीप का पीछा करने का निर्देश दिया। जब वे अंबाला शहर पहुंचे, तो जिस पुलिस वैन में वादी यात्रा कर रहा था, वह जालंदूर शहर की ओर मुड़ गई, लेकिन वैन के चालक को श्री तुली ने करनाल की ओर मुड़ने का निर्देश दिया। जब वैन मजिस्ट्रेट की जीप के पीछे-पीछे शाहबाद पहुंची, तो श्री जगदीश नारायण और अन्य लोगों को ले जाने वाली एक और बस भी आई और फिर मजिस्ट्रेट ने दोनों वाहनों को जालंदूर शहर की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। उस स्तर पर, प्रतिवादी नं। 3, कांस्टेबल ज्ञान चंद, जो पुलिस वैन चला रहे थे, ने कई घंटों तक बिना किसी आराम, राहत या जलपान के निरंतर ड्यूटी के कारण थकान के कारण ड्राइवर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की और राहत पाने का अनुरोध किया। वादी की दलीलों के बावजूद उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें पुलिस वैन को राजपुरा की ओर ले जाने का निर्देश दिया गया। 16 जुलाई, 1957 को लगभग 4 A.M. पर, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया जो सड़क के एक तरफ एक पेड़ से टकरा गया। उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का बायां हाथ कुचल गया और फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद खून बहने लगा। वैन को एस्कॉर्ट करने वाले पंजाब राज्य और उसके पुलिस बल ने वादी और उसके साथियों द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद कोई प्राथमिक उपचार नहीं दिया और उसे लगभग 5 A.M पर एक अनिश्चित स्थिति में राजपुरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें 8.15 A.M पर राजेंद्र अस्पताल, पटियाला ले जाया गया। याचिकाकर्ता ने तब उपचार का क्रम सुनाया और ऊपर बताई गई राशि का दावा किया। प्रतिवादियों द्वारा वाद का विरोध किया गया और निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गएः -

I

—1

1. क्या वादी और उसके दल के अन्य सदस्य किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए 15 जुलाई, 1957 को चंडीगढ़ गए थे?

2. क्या वादी को 15 जुलाई, 1957 से उसकी रिहाई तक प्रतिवादियों द्वारा अवैध कारावास और गैरकानूनी हिरासत में नहीं रखा गया था?

3. क्या प्रतिवादी द्वारा अपनी हिरासत में रहते हुए वादी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जैसा कि पैरा नं. 5 में कहा गया है और क्या यह वादी को मानसिक यातना देने के समान था?

4. क्या दुर्घटना वादी को ले जाने वाली वैन चलाने में प्रतिवादी संख्या 3 की घोर लापरवाही के कारण हुई थी?

5. यदि मुद्दा नं. 4 साबित हो जाता है, क्या प्रतिवादी संख्या 1 दुर्घटना के कारण वादी को हुए नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं है?

6. क्या वादी और प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधि श्री तुली के संज्ञान में यह लाया कि प्रतिवादी संख्या 3 वादी के पैरा 6 और प्रतिवादी संख्या 3 के लिखित कथन के पैरा 6 में बताए गए कारणों से गाड़ी चलाने में असमर्थ था और फिर भी वादी के पैरा 13 में दिए गए कारणों के लिए श्री तुली द्वारा वैन चलाने का आदेश दिया गया था, और यदि ऐसा है, तो इसका क्या प्रभाव है?

7. क्या दुर्घटना ईश्वर का कार्य था?

8. उक्त दुर्घटना के कारण वादी को क्या चोटें आईं?

9. वादी किस राशि के नुकसान का हकदार है और किससे?

10. क्या वाद में समय की पाबंदी है?

11. क्या वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत प्रतिवादियों को वैध नोटिस दिया है?

12. क्या दीवानी न्यायालय के पास विवाद निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?

13. राहत ।

उपर्युक्त मुद्दों पर विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार थेः-1

1. जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वादी और उसके दल के अन्य सदस्य एक संज्ञेय अपराध करने गए थे, सरकार और उसके कर्मचारियों को यह मानने में उचित माना गया कि यह उनका इरादा था।

2. हालांकि प्रक्रिया में कुछ तकनीकी अनियमितताएं थीं, लेकिन स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए वादी का अवरोधन और हिरासत पूरी तरह से अनुचित

नहीं था और कम से कम उन कार्यवाही को करने वाले अधिकारियों के दिमाग में कुछ भी दुर्भावनापूर्ण नहीं था।

3. चंडीमंदिर पुलिस थाने में वादी के साथ किया गया व्यवहार बहुत उचित नहीं था जब यह निश्चित था कि वादी एक उच्च दर्जे का व्यक्ति था, उसने तब तक कोई अपराध नहीं किया था और उस पर नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी मामले का आरोप नहीं लगाया गया था।

4. लापरवाही कर्मचारियों की थी जिसके लिए राज्य उत्तरदायी था।

5. भले ही दुर्घटना अकेले चालक की लापरवाही के कारण हुई हो, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से राज्य जिम्मेदार था।

6. चालक ज्ञान चंद ने थकान आदि के कारण चालक के रूप में अपने कर्तव्य से मुक्त होने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। हालाँकि, उनके अनुरोध की अस्वीकृति का मामले के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ा।

7. दुर्घटना को ईश्वर का कार्य नहीं कहा जा सकता था।

8. दुर्घटना के कारण वादी को चोटें आईं।

9. वादी को एक वकील के रूप में पेशेवर आय के नुकसान और दवाओं आदि पर खर्च की गई राशि के कारण 10,000 रुपये का हकदार ठहराया गया था। दुर्घटना

के परिणामस्वरूप हाथ की स्थायी विकलांगता और दर्द और पीड़ा के कारण वह 30,000 रुपये के भी हकदार थे। चंडीमंदिर पुलिस थाने में अपनी गिरफ्तारी और नजरबंदी के कारण वह किसी भी राशि का हकदार नहीं था। ..

10. मुकदमा सीमा अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 22 के तहत समय के भीतर था और उस अनुसूची का अनुच्छेद 2 लागू नहीं हुआ था।

11. वादी द्वारा प्रतिवादियों को धारा 80, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक वैध नोटिस दिया गया था।

12. इस मुद्दे पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा बहस नहीं की गई थी और इस प्रकार उनके खिलाफ निर्णय लिया गया था।

नतीजतन, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी 1 और 3 के खिलाफ 40,000 रुपये का फरमान पारित किया गया। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रतिवादी संख्या 2) श्री ए. के. कौल के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। पंजाब राज्य को वाद में निर्धारित राशि के संबंध में वादी को आनुपातिक लागत का भुगतान करने और

उस राशि के संबंध में लागत की वसूली करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था जिसके लिए उसे खारिज कर दिया गया था। उस फरमान के खिलाफ पंजाब राज्य ने वर्तमान अपील दायर की है।

विद्वत महाधिवक्ता द्वारा तीन बिंदुओं पर तर्क दिया गया है, अर्थात्, (1) वाद समय द्वारा वर्जित था; (2) पंजाब राज्य उत्तरदायी नहीं था क्योंकि दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को चोटें आईं, तब हुई जब चालक राज्य के प्रत्यायोजित संप्रभु कार्यों के निष्पादन में कार्य कर रहा था और (3) हाथ की स्थायी विकलांगता आदि के कारण हर्जाने के रूप में दी गई 30,000 रुपये की राशि अत्यधिक है। किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं दिया गया है और इसलिए, मुझे उन अन्य बिंदुओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

जहां तक परिसीमा का संबंध है, महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह मामला भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 2 द्वारा शासित है, जो निम्नानुसार है:-

वाद का विवरण	सीमा की अवधि	वह समय जहां से अवधि चलना शुरू होती है
2. भारत में फिलहाल लागू किसी अधिनियम के अनुसरण में कथित कार्य करने या करने से छूटने के लिए [illegible]	नब्बे दिन.	जब कोई कार्य या चूक होती हो ।

दूसरा अनुच्छेद, जिसे मामले में लागू माना गया है, वह अनुच्छेद 22 है जो निम्नानुसार है: -

	वाद का विवरण.	सीमा की अवधि	वह समय जहां से अवधि चलना शुरू होती है
22.	व्यक्ति को किसी अन्य चोट के लिए मुआवजे के लिए।	एक वर्ष	जब चोट लग जाती है

तर्क का भार यह है कि प्रतिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता और पुलिस अधिनियम द्वारा राज्य और पुलिस पर लगाए गए कर्तव्यों के प्रदर्शन में पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 149 का संदर्भ दिया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि उस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में लिया गया था और उसे दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। यह खंड इस प्रकार हैः-"149. संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस-प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकता है, और अपनी क्षमता के अनुसार, किसी भी संज्ञेय अपराध को होने से रोक सकता है।

इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उस शक्ति का प्रयोग 15 जुलाई, 1957 की सुबह किया गया था, जब प्रतिवादी को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इसके बाद उन्हें आधी रात तक वहां हिरासत में रखा गया और फिर उन्हें अपने साथियों के साथ अंबाला की ओर जाने वाली बस में ले जाया गया, और रास्ते में उन्हें एक पुलिस वैन में स्थानांतरित कर दिया गया जो दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना या किसी सक्षम अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी के किसी वारंट के संबंध में गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया था। हालाँकि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उसे आधी रात तक पेश नहीं किया गया। श्री ए. सी. तुली, उप सचिव, वित्त, पंजाब सरकार, जिन्हें अंबाला जिले के मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां दी गई थीं, को सरकार से हिंदी रक्षा समिति के आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की सहायता करने के

आदेश प्राप्त हुए। उन निर्देशों का पालन करते हुए, श्री तुली को चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन से जालंदूर तक एक जत्था ले जाना था, जबकि श्री कपूर को कमल के पास एक जत्था ले जाना था। उस व्यवस्था के अनुसरण में प्रत्यर्थी पुलिस वैन में बैठा था और जब दल अंबाला पहुँचा तो श्री तुली, जो पुलिस वैन से आगे जा रही जीप में थे, जालंदूर की ओर मुड़े, लेकिन पुलिस वैन कमल की ओर चली गई। जब श्री तुली ने कुछ दूरी तय की, तो उन्होंने पीछे देखा कि वैन उनकी जीप का पीछा नहीं कर रही थी। इसलिए, वह अंबाला की ओर मुड़ा और कमल की ओर इस धारणा में गया कि वैन उस तरफ गई होगी। वह शाहबाद में उस वैन से मिला और ड्राइवर को करनाल की जगह जालंदूर की ओर बढ़ने के लिए कहा। शाहबाद से राजपुरा के रास्ते में, चालक को नींद आ गई जिसके परिणामस्वरूप वैन एक पेड़ से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को कई चोटें आईं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी और उसके साथियों को पुलिस वैन में पहुँचाने का उद्देश्य उन्हें किसी स्थान पर तितर-बितर करना था और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना नहीं था, क्योंकि उस समय प्रत्यर्थी या उसके साथियों द्वारा कोई अपराध या कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया था, इसलिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी को चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन से अंबाला और फिर जालंदूर की ओर ले जाने की कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के अनुसरण में नहीं कहा जा सकता था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 और 128 भी उस समय लागू नहीं थीं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस की चंडीमंदिर पुलिस थाने से निवेदन लेने की कार्रवाई भारत में फिलहाल लागू किसी अधिनियम के अनुसरण में थी।

पुलिस अधिनियम की धारा 23, जिस पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी

गई है, निम्नानुसार है -

> प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तुरंत पालन करे और उन्हें निष्पादित करे; सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली खुफिया जानकारी एकत्र करे और उसे कार्यान्वित करे; अपराधों और सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए; अपराधियों का पता लगाए और उन्हें न्याय के दायरे में लाए और उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिन्हें वह कानूनी रूप से गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, और जिनकी आशंका के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है; और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए, इस धारा में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए, बिना वारंट के, किसी शराब की दुकान, जुआघर या खुले और अव्यवस्थित पात्रों के आश्रय के अन्य स्थान में प्रवेश करना और निरीक्षण करना विधिसम्मत होगा।

> इस धारा का भी कोई आवेदन नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी को 15 जुलाई, 1957 की सुबह पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरी राय में, इसलिए, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 2 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और मामला उस अधिनियम के अनुच्छेद 22 द्वारा शासित है और दुर्घटना की तारीख के एक वर्ष के भीतर दायर किया गया है, इसलिए मुकदमे को समय द्वारा वर्जित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।

विचार के लिए अगला बिंदु यह है कि क्या पुलिस वैन को राज्य की किसी प्रत्यायोजित संप्रभु शक्ति के प्रयोग में चालक ज्ञान चंद द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि राज्य में कानून और व्यवस्था का संरक्षण राज्य का संप्रभु कार्य है, लेकिन किसी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके तितर-बितर

करने की दृष्टि से राज्य की पसंद के स्थान पर पहुँचाना एक संप्रभु कार्य नहीं कहा जा सकता है। एक नागरिक के गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के बाद, उसके साथ देश के कानून के तहत व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि राज्य के अधिकारियों की सनक के अनुसार। किसी भी कानून में राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तितर-बितर करने के लिए कहीं ले जाने का अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि उसे कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कि पुलिस अभिरक्षा में या कहीं और प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी या आशंका और हिरासत के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई वारंट जारी नहीं किया गया था, और इसलिए, किसी अज्ञात गंतव्य के लिए पुलिस वैन में उसका परिवहन राज्य के संप्रभु कार्य के प्रदर्शन में नहीं कहा जा सकता था। पुलिस वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को हुई चोटों के लिए राज्य सरकार स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है।

अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि चालक की गलती थी और वह अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही कर रहा था। उन्होंने मजिस्ट्रेट श्री ए. सी. तुली से शिकायत की थी कि उन्हें इस आधार पर वाहन चलाने के कर्तव्य से मुक्त किया जाए कि वह थकान और थकावट से पीड़ित थे क्योंकि उन्हें पिछले दो या तीन दिनों के दौरान कोई आराम या राहत नहीं दी गई थी। उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था और परिणाम स्वरूप थकावट के प्रभाव में उन्हें नींद आ गई और उन्होंने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। ड्राइवर को झपकी आने को भगवान का कार्य नहीं कहा जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष कहा था। दुर्घटना चालक की ओर से लापरवाही के

परिणामस्वरूप हुई और राज्य सरकार, उसके नियोक्ता के रूप में, उस दुर्घटना में प्रतिवादी को हुई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा सही ढंग से तय किया गया है।

विचार करने की आवश्यकता वाला एकमात्र अन्य बिंदु यह है कि क्या अस्पताल में उपचार की अवधि के दौरान चोटों और शारीरिक और मानसिक दर्द और पीड़ा के परिणामस्वरूप उसे हुई स्थायी विकलांगता के कारण प्रतिवादी को दी गई 30,000 रुपये की राशि अत्यधिक है। प्रतिवादी को निम्नलिखित चोटें आई थीं: -

'• 1. इसके निचले हिस्से में बाएं ऊपरी हाथ के पीछे के हिस्से पर बड़ा घाव और यह कोहनी के नीचे अग्र-भुजा के बीच तक फैला हुआ था। इसके ऊपरी भाग में अल्ना का फ्रैक्चर था और ऊपरी रेडियो अल्नर जोड़ का विस्थापन था और त्रिज्या का सिर और टूटे हुए अल्ना के निचले टुकड़े का ऊपरी छोर घाव से बाहर निकल रहा था। इफ़ 'के आसपास हड्डी का एक अलग हिस्सा था जो लंबे समय से हड्डी से गिरा हुआ था लेकिन मांसपेशियों से जुड़ा हुआ था। हड्डी के कुछ अन्य छोटे टुकड़े भी इसी तरह पड़े हुए थे। मांसपेशियाँ बुरी तरह से फटी हुई थीं। घाव के आयाम 10 "x 5" थे।

2. ह्यूमरस के बीच में बाएं हिस्से का फ्रैक्चर।

3. घाव अण्डाकार, बाएं अग्र-भुजा के पोस्टरोलेटरल पहलू पर 3 "x 1J"। जगह-जगह मांसपेशियाँ फटी हुई थीं। कुछ मांसपेशियों के पेट स्टिमुली तक नहीं पहुंच रहे थे और खून नहीं बह रहा था। विभाग द्वारा फ्रैक्चर के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई और किया गया, जिससे पता चला: -

(i) इसके मध्य शाफ्ट के पास कम्यूनिकेटेड फ्रैक्चर ह्यूमरस हड्डी। स्तर पर कोई कॉलस गठन नहीं है।

(ii) एलेक्रोनॉन प्रक्रिया के साथ इसके शाफ्ट के संगम पर अल्ना हड्डी के ऊपरी भाग का कम्यूनिकेटेड फ्रैक्चर। कोई कॉलस अलग नहीं हुआ।

(iii) त्रिज्या हड्डी के ऊपरी हाथ के सिर और गर्दन को जोड़ते हुए एक कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कोई कॉलस नहीं पाया गया।

लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। इस मुद्दे पर प्रतिवादी का बयान इस प्रकार हैः-"पुलिस स्टेशन चंडीमंदिर में मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह अपमानजनक और अमानवीय था। वी. जे. अस्पताल में रहने के दौरान मैं लगभग एक महीने तक भी नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं अपने बिस्तर से शौचालय तक नहीं जा सकता था। मुझे उस महीने भर बिस्तर पर रहना पड़ा। चिकित्सा उपचार के परिणामस्वरूप मुझे ऊर्ध्वाधर आकार में ऊपर की ओर बंधी पट्टियों में अपनी बांह के साथ बिल्कुल सपाट लेटना पड़ा। मेरे हाथ के घावों से निकलने वाले खून और मवाद से ऐसी बदबू आ रही थी कि कोई भी शरीर मेरे कमरे से गुजर नहीं सकता था। घावों को पहले धोने के लगभग एक महीने बाद धोया गया था। मैंने 14 महीनों की अवधि के दौरान लगातार लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान सहन किया जब मैं शुरुआत में राजिंद्रा अस्पताल, पटियाला में रहा। जब मैं राजिंदरा अस्पताल से निकला तो यह 104 डिग्री से घटकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। मेरा हर दिन कई इंजेक्शनों से इलाज किया जाता था और इंजेक्शनों ने मेरे कूल्हों को काला कर दिया। राजेंद्र अस्पताल में

रहते हुए मेरे शरीर की थोड़ी सी हरकत ने मुझे बहुत दर्द दिया। मेरी छोटी उंगली और तर्जनी में अब भी कोई हलचल नहीं है। मेरे बाएं हाथ की चारों उंगलियों को पीछे की ओर नहीं ले जाया जा सकता है। वे हमेशा झुकी हुई स्थिति में रहते थे। कलाई का हिलना-डुलना बंद हो गया है यानी कलाई का हिलना-डुलना नहीं बचा है। मेरे बाएं हाथ की कोहनी में दोनों तरफ कोई हलचल नहीं है। मेरे बाएं हाथ का कंधा हमेशा 'एन' स्थिति में रहता है। मैं अपने कंधे को ऊपर या पीछे नहीं उठा सकता। मैं अपने सिर, चेहरे, दाहिने कंधे और कमर और पीठ के दाहिने हिस्से को छू नहीं सकता। इस प्रकार मुझे नहाते समय बहुत कठिनाई महसूस होती है। अगर मेरा दाहिना हाथ भरा हुआ है, तो मैं मच्छरों, मक्खियों और अन्य कीड़ों को हटाने में भी मदद नहीं कर सकता अगर वे मेरे शरीर पर बैठते हैं या उससे चिपक जाते हैं। चूँकि इस भुजा में बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, एक अजीब दर्द तब शुरू होता है जब यह लगभग 15 मिनट तक लगातार स्थिर स्थिति में रहता है। मुझे हमेशा बात करते समय, चलते समय, बैठते समय और कोई अन्य काम करते समय अपना बायां हाथ दबाते रहना पड़ता है। मेरी नींद लगभग हर दो घंटे के बाद टूट जाती है क्योंकि मैं सोते समय बाईं ओर मोड़ नहीं ले सकता। सोते समय यह भुजा ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री कोण की स्थिति में रहती है, क्योंकि अग्रभुजा की मांसपेशियों को अग्रभुजा के सामने की ओर लगाने के बजाय चिकित्सा कर्मियों द्वारा भुजा के पीछे लगाया गया था। मुझे हाथ में लगातार दर्द महसूस होता है।"

उपर्युक्त साक्ष्य, प्रतिवादी द्वारा झेली गई मानसिक और शारीरिक पीड़ा, लगी चोटों और उसके परिणामस्वरूप उसकी भुजा की स्थायी विकलांगता को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुआवजे के रूप में उसे दी गई 30,000 रुपये की राशि, किसी भी तरह से, अत्यधिक है। प्रत्यर्थी एक वकील है और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल का

एक प्रतिष्ठित नेता है और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए, उसे उसके द्वारा झेली गई पीड़ाओं के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। [1]

पेशेवर आय के नुकसान और दवाओं की लागत आदि के कारण प्रत्यर्थी को दिए गए 10,000 रुपये की राशि को भी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया है और विद्वान महाधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष विवादित नहीं किया गया है।

नतीजतन, अपील बिना किसी योग्यता के है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा